भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1991

29 अगस्त, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग में संकट

1991. श्री नंद कुमार साय:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वस्त्र उद्योग पर संकट छाया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने ऋण के बोझ से दबे वस्त्र उद्योग के लिए ऋण का पुनर्निधारण किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तेजी से पुनर्निधारण किए जाने हेतु उद्योग-बैंकों से समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)</u>

(क) से (ग): वस्त्र मंत्री ने वस्त्र उद्योग के ऋण पुनर्गठन के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा है । वस्त्र उद्योग पर दबाव की सीमा के बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा केपिटल मार्किट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन ने वस्त्र उद्योग में 155,809 करोड़ रु. का कुल निधि आधारित ऋण अभिज्ञात किया है और 35,000 करोड़ रु. के संकटग्रस्त ऋण की मात्रा का अनुमान लगाया है । बैंक ऑफ बड़ौदा की सिफारिशें वित्त मंत्री द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं । भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:-

(i) द्वितीय पुनर्गठन पर परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ का मामला औचित्यपूर्ण नहीं है ।

(ii) प्रावधानीकरण पर मांगी गई रियायत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्याशित हानियों के लिए प्रावधानीकरण प्रथम सुरक्षा है ।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल धनराशि के पुर्नभुगतान पर ऋण स्थगन और कार्यशील पूंजी को 3-5 वर्षों की अवधि में भुगतान योग्य कार्यशील पूंजी आवधिक ऋणों में परिवर्तित करने के संबंध में 'अनापत्ति' व्यक्त की है ।

(घ) और (ड.): जी, हां । ऋणों के पुनर्गठन हेतु बैंकों एवं वस्त्र उद्योग में समन्वय के लिए सरकार द्वारा 13 जून, 2012 को एक अधिकारी समूह का गठन किया गया है । इस अधिकारी समूह ने 13 जुलाई, 2012 को बैठक की है । सरकार ने वस्त्र उद्योग को, बैंकों द्वारा अग्रिमों के पुनर्गठन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुरूप अलग-अलग मामले के आधार पर वस्त्र उद्योग के ऋणों को पुनर्गठित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।